



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 8 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 17, 1944 शक सम्बत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1939/वि०स०/संसदीय/161(सं०)-2022

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 6 दिसम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2022 कहलायेगा।

2-ऐसे विविध परिचय्य चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2023 ई० को समाप्त होने वाले उत्तर प्रदेश राज्य की वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, समेकित निधि में से वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा 2022-23 के लिए सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 33769,54,67,000 रुपये 33769,54,67,000 रुपये (रुपये तैंतीस हजार सात सौ उनहत्तर करोड़ चौवन लाख सड़सठ हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग 3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत राज्य की समेकित निधि पर भारित योग
02	आवास विभाग	पूंजी : 400000.00 -- 400000.00
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी : 30000.00 -- 30000.00
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व : 106990.69 -- 106990.69
		पूंजी : 820000.00 -- 820000.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व : 525772.00 91.41 525863.41
		पूंजी : 65072.32 535.00 65607.32
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व : 19027.00 -- 19027.00
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व : 14.77 -- 14.77
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व : 8472.91 -- 8472.91
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पूंजी : 1500.00 -- 1500.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व : -- 193.30 193.30
22	खेल विभाग	राजस्व : 3500.00 -- 3500.00
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व : 15500.00 -- 15500.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	पूंजी : 5000.00 -- 5000.00
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व : 20000.00 -- 20000.00
		पूंजी : 45000.00 -- 45000.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व : 23900.75 -- 23900.75
		पूंजी : 750.00 -- 750.00

अनुसूची					
--(क्रमशः):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रूपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी :	2000.00	--	2000.00
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	169206.76	--	169206.76
		पूंजी :	98751.33	--	98751.33
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	92400.00	--	92400.00
		पूंजी :	52155.00	--	52155.00
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	1618.60	--	1618.60
		पूंजी :	30000.00	--	30000.00
42	न्याय विभाग	पूंजी :	40000.00	--	40000.00
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	10000.00	--	10000.00
		पूंजी :	20000.00	--	20000.00
44	पर्यटन विभाग	पूंजी :	2000.00	--	2000.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	6493.56	--	6493.56
		पूंजी :	5833.00	--	5833.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	50000.00	--	50000.00
		पूंजी :	183792.00	--	183792.00
60	वन विभाग	राजस्व :	10.08	--	10.08
		पूंजी :	25650.92	--	25650.92
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	25136.00	--	25136.00
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	19646.00	--	19646.00
		पूंजी :	7500.00	--	7500.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	252.00	--	252.00
		पूंजी :	908.47	--	908.47
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	17741.70	--	17741.70

अनुसूची					
--(क्रमशः)--					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
		(लाख रुपयों में)			
क्रम		विधान सभा द्वारा	राज्य की समेकित निधि पर	योग	
संख्या		स्वीकृत	भारित		
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	5500.00	--	5500.00
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक	पूंजी :	1023.80	--	1023.80
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)				
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	3075.52	--	3075.52
		पूंजी :	17278.00	--	17278.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	30.43	--	30.43
		पूंजी :	37.80	--	37.80
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	15000.00	--	15000.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन	राजस्व :	41626.66	--	41626.66
	सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग				
	कल्याण)	पूंजी :	600.00	--	600.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति	राजस्व :	13903.28	--	13903.28
	कल्याण)	पूंजी :	3612.24	--	3612.24
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित	राजस्व :	99512.65	--	99512.65
	जातियों के लिये विशेष घटक				
	योजना)	पूंजी :	137780.13	--	137780.13
84	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी :	1610.00	--	1610.00
86	सूचना विभाग	राजस्व :	80420.56	--	80420.56
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	647.65	--	647.65
		पूंजी :	500.00	--	500.00
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति	पूंजी :	2380.39	--	2380.39
	विभाग				

अनुसूची					
(समाप्त):					
1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक			
(लाख रुपयों में)					
क्रम	विधान सभा द्वारा		राज्य की समेकत निधि पर	योग	
संख्या	स्वीकृत		भारित		
	योग :	राजस्व :	1375399.57	284.71	1375684.28
		पूंजी :	2000735.39	535.00	2001270.39
	महायोग :		3376134.96	819.71	3376954.67

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2022-2023 का अनुपूरक) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना,
वित्त मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 606/XC-S-1-22-27S--2022
Dated Lucknow, December 8, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Vinayog (2022-2023 Ka Anupoorak) Vidheyak, 2022" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 6, 2022.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SUPPLEMENTARY 2022-2023)
BILL, 2022

A
BILL

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2023.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:—

Short title	1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Supplementary 2022-2023) Act, 2022.
Issue of Rs. 33769,54,67,000 out of the Consolidated Fund of the state of Uttar Pradesh for the year 2022-2023	2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 33769,54,67,000 (Rs. Thirty three thousand seven hundred sixty nine crore fifty four lac sixty seven thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2023 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.
Appropriation	3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the state of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2023.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
02	Housing Department Capital :	400000.00	--	400000.00
03	Industries Department (Small Industry and Export Promotion) Capital :	30000.00	--	30000.00
07	Industries Department (Heavy and Medium Industries) Revenue :	106990.69	--	106990.69
	Capital :	820000.00	--	820000.00
09	Power Department Revenue :	525772.00	91.41	525863.41
	Capital :	65072.32	535.00	65607.32
11	Agriculture and Other Allied Departments (Agriculture) Revenue :	19027.00	--	19027.00
12	Agriculture & Other Allied Departments (Land Development & Water Resources) Revenue :	14.77	--	14.77
13	Agriculture and Other Allied Departments (Rural Development) Revenue :	8472.91	--	8472.91
14	Agriculture and Other Allied Departments (Panchayati Raj) Capital :	1500.00	--	1500.00
18	Agriculture and Other Allied Departments (Cooperative) Revenue :	--	193.30	193.30
22	Sports Department Revenue :	3500.00	--	3500.00
23	Cane Development Department (Cane) Revenue :	15500.00	--	15500.00
24	Cane Development Department (Sugar Industry) Capital :	5000.00	--	5000.00
26	Home Department (Police) Revenue :	20000.00	--	20000.00

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
	Capital :	45000.00	--	45000.00
31	Medical Department (Medical Education and Training)	Revenue : 23900.75	--	23900.75
	Capital :	750.00	--	750.00
32	Medical Department (Allopathy)	Capital : 2000.00	--	2000.00
35	Medical Department (Family Welfare)	Revenue : 169206.76	--	169206.76
	Capital :	98751.33	--	98751.33
37	Urban Development Department	Revenue : 92400.00	--	92400.00
	Capital :	52155.00	--	52155.00
40	Planning Department	Revenue : 1618.60	--	1618.60
	Capital :	30000.00	--	30000.00
42	Judicial Department	Capital : 40000.00	--	40000.00
43	Transport Department	Revenue : 10000.00	--	10000.00
	Capital :	20000.00	--	20000.00
44	Tourism Department	Capital : 2000.00	--	2000.00
49	Women & Child Welfare Department	Revenue : 6493.56	--	6493.56
	Capital :	5833.00	--	5833.00
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Revenue : 50000.00	--	50000.00

SCHEDULE

--(Contd):

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
		Capital :	183792.00	--	183792.00
60	Forest Department	Revenue :	10.08	--	10.08
		Capital :	25650.92	--	25650.92
61	Finance Department (Debt Services and Other Expenditure)	Revenue :	25136.00	--	25136.00
69	Vocational Education Department	Revenue :	19646.00	--	19646.00
		Capital :	7500.00	--	7500.00
70	Science and Technology Department	Revenue :	252.00	--	252.00
		Capital :	908.47	--	908.47
71	Education Department (Primary Education)	Revenue :	17741.70	--	17741.70
72	Education Department (Secondary Education)	Revenue :	5500.00	--	5500.00
75	Education Department (State Council of Education Research & Training)	Capital :	1023.80	--	1023.80
76	Labour Department (Labour Welfare)	Revenue :	3075.52	--	3075.52
		Capital :	17278.00	--	17278.00
77	Labour Department (Employment)	Revenue :	30.43	--	30.43
		Capital :	37.80	--	37.80
78	Secretariat Administration Department	Revenue :	15000.00	--	15000.00
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of	Revenue :	41626.66	--	41626.66

SCHEDULE

(Contld):

1	2	3		
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding		
		(In lakhs)		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total
	Backward Classes)			
	Capital :	600.00	--	600.00
81	Social Welfare Department (Tribal Welfare) Revenue :	13903.28	--	13903.28
	Capital :	3612.24	--	3612.24
83	Social Welfare Department (Special Component Plan for Scheduled Castes) Revenue :	99512.65	--	99512.65
	Capital :	137780.13	--	137780.13
84	General Administration Department Capital :	1610.00	--	1610.00
86	Information Department Revenue :	80420.56	--	80420.56
92	Culture Department Revenue :	647.65	--	647.65
	Capital :	500.00	--	500.00
93	Namami Gangey and Rural Water Supply Department Capital :	2380.39	--	2380.39
	Total ;	Revenue : 1375399.57	284.71	1375684.28
		Capital : 2000735.39	535.00	2001270.39
	Grant Total :	3376134.96	819.71	3376954.67

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary expenditure *charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2022-2023.

The Uttar Pradesh appropriation (Supplementary 2022-2023) Bill, 2022 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA

Vitt Mantri.

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.